आदर्श हिमाचल

Aadarshhimachal.com | aadarshhimachal@gmail.com

खबरें विकास की, मुद्दे जनता के

शिमला 30 जनवरी से 05 फरवरी, 2023 | RNI No. HPHIN/2017/70267 | ◆ वर्ष 8 ◆ अंक 06

बेसहारा पशुओं को मिलेगा आश्रय, सुक्खू ने पशुपालन विभाग को दिए ये कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्प लाइन, 1100 पर लोग कर सकते है बेसहारा पशुओं से सम्बन्धित जानकारी व शिकायत दर्ज

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में वंचित वर्गों के कल्याण को सर्वोच्च अधिमान दिया है। इसके साथ.साथ सरकार बेसहारा पशुओं के कल्याण के लिए भी बहुआयामी कदम उठा रही है। शुक्रवार सायं शिमला में गौ सेवा आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पशुपालन विभाग को बेसहारा पशुओं आश्रय प्रदान करने के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्प लाइन.1100 के माध्यम से लोग बेसहारा पशुओं से सम्बन्धित जानकारी व शिकायत कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को इस सम्बंध में एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित करने के निर्देश दिए जिसमें कि बेसहारा पशुओं के छायाचित्र अपलोड किए जा सकें।

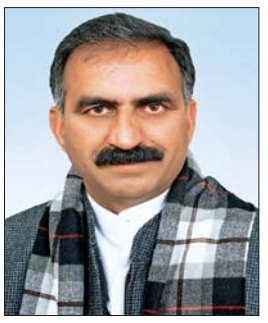

उपनिदेशक उन्होंने कहा कि लोगों से शिकायत प्राप्त होने के उपरांत यह सूचना सम्बन्धित खण्ड के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी एवं फार्मासिस्ट से साझा की जाएगी और यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि बेसहारा पशु को गौ सदन या अन्य उपयुक्त स्थल में पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए इस हेल्पलाइन के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाना चाहिए।

मु मुख्यमंत्री ने कहा कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में 36,311 बेसहारा पशु हैंए जिनमें से 20,203 बेसहारा पशुओं को विभिन्न गौ सदनों में आश्रय प्रदान किया गया है और अभी भी 9ए117 बेसहारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पशुओं को बेहतर आश्रय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मौजूदा गौशालाओं के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए पशुपालन विभाग के अधिकारी वन विभाग की सहायता से चरागाह और जल स्त्रोतों के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करें। उन्होंने अधिकारियों को पशुओं की देखभाल के लिए रात्रि आश्रय निर्मित करने और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में 10 दिन के भीतर कार्य योजना तैयार करने के मुख्यमंत्रीनिर्देश दिए।

मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की सुविधा के लिए बेसहारा पशुओं से उत्पन्न समस्या तथा इनके कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के निवारण के लिए पूर्ण गंभीरता के साथ कार्य कर रही है और इसके लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा।

कृषि एवं पशुपालन मंत्री चन्द्र कुमार ने कहा कि विभागीय अधिकारी बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए फील्ड में गंभीरता से कार्य करें और इस समस्या के निवारण के लिए गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लें। उन्होंने इस दिशा में व्यावहारिक कदम उठाने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार गोकुल बुटेल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, पशुपालन सचिव अजय शर्मा, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सिर्फ रस्म अदायगी के लिए पेश किया गया केंद्रीय बजट : सुक्खू

बोले हिमाचल के साथ दिल्ली और पंजाब जैसे कई राज्यों पर है कर्ज का बोझ

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला । वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निराशाजनक करार दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बजट को केवल रस्म अदायगी के लिए पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में न तो आम आदमी की नजर आ रहा है और न ही हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के साथ दिल्ली और पंजाब जैसे कई राज्य कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को इन राज्यों के बारे में विचार करना चाहिए थाए उन्होंने कहा कि सरकार को कर्ज के बोझ तले इन राज्यों के लिए एक विशेष पैकेज घोषित करना चाहिए थाए लेकिन बजट में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को लेकर बात कही गई थीए लेकिन इस बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद भी मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश की मुद्दों को केंद्र के सामने रखा। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश का बजट में कुछ उन्होंने केंद्रीय बजट को पूरी तरह निराशाजनक करार दिया।

परिवहन विभाग ने खरीदी 19 इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सभी आरटीओ कार्यालय में खुलेगें चार्जिंग स्टेशन

शिमला। हिमाचल में परिवहन विभाग ने 19 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद की है जिसमें प्रदेश के सभी आरटीओ को यह इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी खुलेंगे। प्रदेश सरकार के आदेशों पर परिवहन विभाग ने इन 19 इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद ली है। इन 18 गाड़ियों में से 11 शिमला पहुंच गई हैं जबकि 8 गाड़ियां तीन से चार दिन में पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा गाड़ियों के चार्जर भी सभी आरटीओ कार्यालयों में लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीमार महिला को लाहौल से किया गया एयर लिफ्ट

पदमा देचिन का कुल्लू अस्पताल में किया जा रहा है उपचार

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जिला लाहौल.स्पिति के उदयपुर उपमंडल के गांव छालिंग निवासी पदमा देचिन गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा की आवश्यकता है। यह जानकारी प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री ने पदमा देचिन को हेलिकॉप्टर के माध्यम से कुल्लू स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने दिए विभिन्न विभागों को खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत विकास योजनाएं तैयार करने के निर्देश प्रशासन ने बिना समय गंवाए मुख्यमंत्री के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की। अब पदमा देचिन का कुल्लू अस्पताल उपचार किया जा रहा है। भारी बर्फबारी से सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण पदमा देचिन का उपचार घाटी में संभव नहीं हो पा रहा था और उन्हें इसके लिए कुल्लू स्थानांतरित करना अत्यंत आवश्यक था। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदनाओं को सर्वोच्च अधिमान देते हुए पदमा देचिन का उपचार करवाने के लिए प्रशासन को तुरंत हेलिकॉप्टर का प्रबंध कर उन्हें कुल्लू स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। यह सुख की सरकार के मानवीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री जरूरतमंदों और विपरीत परिस्थितियों से घिरे प्रदेशवासियों के लिए चिंतित रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में फंसे किसी भी प्रदेशवासी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री त्वरित निर्णय लेकर उसका समाधान सुनिश्चित करते हैं।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की केंद्रीय बजट की प्रशंसा, कहा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पेश हुआ ऐतिहासिक बजट

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला । देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2ण्0 का बजट पेश कियाण् सरकार के इस बजट को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में से भी जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद पक्ष.विपक्ष की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस बजट को आत्मनिर्भर भारत की ओर सशक्त कदम करार दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ऐतिहासिक और सराहनीय बजट पेश किया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस बजट से भारत आर्थिक तौर पर मजबूती की ओर बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि निर्धन, ग्रामीण, मजदूर, मध्यम वर्ग किसान, कर्मचारी, महिला, बुजुर्गों और विद्यार्थियों को इस बजट में राहत देने का काम किया गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी आभार व्यक्त किया।

अटल टनल, रोहतांग समेत चोटियों पर बर्फबारी सोलंगनाला से आगे नहीं जाने दिए पर्यटक वाहन

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल, रोहतांग समेत प्रदेश की अन्य ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। सोमवार दोपहर बाद अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के साथ पूरी घाटी में रुक-रुककर बर्फबारी होती रही। चंबा के भरमौर, चुराह और किन्नौर की चोटियों पर भी हिमपात हुआ है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। वहीं, बर्फबारी शुरू होने के बाद पुलिस ने लाहौल के सिस्सू व कोकसर घूमने गए सैलानियों को वापस मनाली भेजा। क्रिसमस के लिए मनाली पहुंचे हजारों सैलानी बर्फ देखने के लिए अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल पहुंचे थे। लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और बर्फबारी शुरू हो गई। अधिक बर्फबारी होने की आशंका को देखते हुए मनाली पुलिस ने शाम 4.00 बजे के बाद सोलंगनाला से आगे पर्यटकों के वाहनों को नहीं जाने दिया। लाहौल की ओर सिर्फ स्थानीय लोगों के वाहनों को ही जाने दिया गया। मैदानी जिलों में धुंध पड़ने का सिलसिला जारी है। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। सोमवार को राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। रविवार रात को केलांग और कल्पा का न्यूनतम पारा माइनस में दर्ज हुआ है।

दो दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में वीरवार और शुक्रवार को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 29 और 30 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश के अन्य जिलों में इस दौरान बारिश के आसार हैं। 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। ऊंचे इलाकों की ओर न जाएं सैलानी क्रिसमस के बाद कुल्लू-मनाली और लाहौल के सिस्सू और कोकसर में नए साल के जश्न के लिए काफी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आज और कल बारिश और बर्फबारी की संभावना के चलते जिला कुल्लू के साथ लाहौल-स्पीति प्रशासन ने सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। खासकर पर्यटकों को अटल टनल रोहतांग, हामटा पास और जलोड़ी दर्रे का रुख न करने की हिदायत दी है। हिमाचल परिवहन निगम ने भी बस चालकों को खराब मौसम तथा तापमान गिरने से जम रही सड़कों पर किसी तरह का जोखिम न उठाने का आग्रह किया है। उपायुक्त लाहौल-स्पीति सुमित खिमटा ने कहा कि अगले दो दिन में सैलानी किसी भी प्रकार के जोखिम से बचने के लिए अधिक ऊंचाई, कम तापमान वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने से बचें। उन्होंने ग्राम पंचायत प्रधानों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रैकरों और पैदल चलने वालों से आग्रह किया है कि वह मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर ही यात्रा करें। मौसम और सड़क या किसी प्राकृतिक आपदा और घटना की स्थिति में जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से 94594-61355, 01900-202509, 510, 517 और टोल फ्री 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरदेव शर्मा ने कहा कि घाटी में आने वाले सैलानी अटल टनल रोहतांग के साथ जलोड़ी दर्रा आदि ऊंचे इलाकों की ओर न जाएं। स्कूलों और कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि विद्यार्थियों को फेस मास्क पहनने के लिए कहा जाए। खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत वाले विद्यार्थियों को कोविड टेस्ट कराने की सलाह भी दी है। शिक्षण संस्थानों में कोविड से बचाव के नियमों के प्रति जागरूक करने को भी कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने जिला उप निदेशकों को जारी पत्र में सभी आवश्यक एहतियात बरतने को कहा है।

खर्चे घटाने में जुटी सुक्खू सरकार का पहला बजट नहीं होगा लोक लुभावन, शराब पर लग सकता है और सेस

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। सुक्खू सरकार के पहले बजट में कई नए सेस और कर शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पिछली जयराम सरकार पर कर्ज में डुबोने का आरोप लगा कड़े फैसले लेने की बात कर चुके हैं। वहीं, चुनावी साल न होने के कारण बजट के लोकलुभावन होने के आसार भी कम बने हुए हैं। संभावना जताई जा रही है कि सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में अपने पहले बजट में जहां शराब पर और सेस लगा सकती है, वहीं कई अन्य विलासिता की वस्तुओं पर भी नए टैक्स लगाए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री पहले ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक सुधारों के लिए कड़े फैसले लिए जाने की जरूरत है। उन्होंने यह बात उस समय कही थी, जब वह ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के लिए बजट का प्रबंध डीजल पर वैट बढ़ाकर करने की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनावी लाभ लेने के लिए सात प्रतिशत वैट कम किया। वर्तमान सरकार ने इसी में तीन फीसदी बढ़ोतरी कर ओपीएस के लिए बजट जुटाया है। उन्होंने प्रदेश की जनता से भी इस बारे में सहयोग की अपील करते हुए कहा था कि आने वाले वक्त में इसी तरह के कड़े फैसले लेने होंगे। सरकार के कड़े फैसले बजट में आर्थिक नियोजन और प्रबंधन में सामने आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय विधायकों से पूछा गया है कि वे बताएं कि राज्य में किस तरह से स्वरोजगार दिया जा सकता है या फिर रोजगार दिया जा सकता है। इसके लिए सभी विधायकों से एक नए प्रारूप पर अपने सुझाव लिखने को कहा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बनाए जा रहे वार्षिक बजट अनुमानों के लिए विधायकों से पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। पहला बिंदु यह है कि हिमाचल प्रदेश में फिजूलखर्ची घटाने के लिए के लिए किन उपायों को किया जाए। दूसरा सुझाव यह पूछा गया है कि राज्य में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए क्या किया जाए। तीसरा सुझाव यह मांगा गया है कि बेहतर प्रशासन के लिए किस तरह के उपायों को अपनाने की जरूरत है। चौथा सुझाव स्वरोजगार और रोजगार सृजित करने के लिए मांगा गया है। किसी भी विकास क्षेत्र में नई नीति के लिए भी सुझाव मांगा गया है। सभी विधायकों को सुझाव 1 और 2 फरवरी को होने जा रही विधायक प्राथमिकता बैठकों से पहले देने को कहा गया है, जिससे कि इन्हें अगले बजट अनुमानों में शामिल किया जा सके।

ट्रक ऑपरेटरों को 31 मार्च तक गुड्स टैक्स जमा कराने की छूट

सोलन। राज्य सरकार प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों को 31 मार्च तक गुड्स टैक्स जमा कराने की छूट दे दी है। सोमवार से यह छूट लागू हो जाएगी। जिन संचालकों के ट्रक बिना परमिट के खड़े हो गए हैं, वे अब इस छूट के बाद ट्रकों की पासिंग और परमिट बना सकते हैं। इसे लेकर मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार ने ट्रक संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें इसकी जानकारी दी।

उन्होंने संचालकों को आश्वासन दिया कि 31 मार्च से पहले ट्रक संचालकों की सरकार के साथ बैठक कर लंबित गुड्स टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर सहमति बनाई जाएगी, ताकि भविष्य में ट्रक संचालकों को यह समस्या न आए। उन्होंने कहा कि बीबीएन में दस हजार ट्रक हैं, जिनमें से 25 फीसदी ट्रक संचालकों ने गुड्स टैक्स जमा नहीं कराया है। हालांकि गुड्स टैक्स तो कम है, लेकिन इस पर पैनल्टी अधिक है। राम कुमार ने ट्रक संचालकों को आश्वासन दिया कि पैनल्टी माफ करने के लिए सरकार से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने बैठक में डिप्टी आरटीओ विद्या देवी को निर्देश दिए कि किसी भी वाहन को बिना कारण न रोका जाए।

उद्योग अच्छा कार्य करेंगे तभी ट्रक संचालकों को काम मिलेगा। इसके लिए वह दोनों के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य रहे हैं। सिंगल विंडो को बंद करके जल्द एक प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारियों को समय सीमा के भीतर ही फाइल निपटानी होगी। कमेटी फाइल सीएम के पास मंजूरी के लिए भेजेगी। अब बिना कारण सचिवालय घूमने के बजाय सीधे सीएम से स्वीकृति ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने यूनियन को कमजोर करने का प्रयास किया था।

मनाली में बर्फबारी के दौरान एक सुंदर दृश्य

बागवानों की मांगों को पूरा करने की घोषणा करे सरकार

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। किसानों-बागवानों के मुद्दों को लेकर संघर्षरत संयुक्त किसान मंच ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को 20 सूत्रीय मांगपत्र भेजकर बजट में मांगें पूरी करने की घोषणा करने की अपील की है। मंच ने मुख्यमंत्री से मांगों पर चर्चा के लिए किसान बागवानों के साथ जल्द बैठक करने की भी मांग उठाई है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान ने कहा कि पिछली सरकार ने मंच की मांगों की अनदेखी की।

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंच के साथ बैठक में मांगें गंभीरता से तो सुनीं, लेकिन एक भी मांग पूरी नहीं की। संयुक्त किसान मंच के आंदोलन में मौजूदा सरकार के विधायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र और गारंटियों में भी मुद्दों को जगह दी गई थी। मंच को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री किसानों-बागवानों की मांगों पर गंभीरता दिखाएंगे और आगामी बजट में मांगें पूरी करने की घोषणा करेंगे।

मांगपत्र में ये मांगें उठाईं

फल, फूल, सब्जी के पैकिंग कार्टन पर जीएसटी खत्म कर कार्टन ट्रे की कीमतें घटाएं, एचपीएमसी, हिमफेड बागवानों के बकाया 90 करोड़ रुपये का तुरंत भुगतान हो, कश्मीर की तर्ज पर एमआईएस के तहत ए, बी, सी ग्रेड सेब क्रमशः 60, 44 और 24 रुपये प्रति किलो खरीदें, खाद, बीज, कीटनाशक व अन्य लागत वस्तुओं पर अनुदान बहाल कर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध करवाएं, सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी कर इसे मुक्त व्यापार संधि से बाहर करें, बागवानी विकास के लिए बागवानी बोर्ड व आय आयोग का गठन करें, मंडियों में एपीएमसी कानून को सख्ती से लागू करें, बैरियरों पर ली जा रही मार्किट फीस वसूली पर रोक लगाकर शोघी बैरियर बंद करें।

प्रदेश की सभी मंडियों में सेब व अन्य फसलें वजन के हिसाब से बेची जाएं, आढ़तियों व खरीदारों के पास बकाया पैसों का तुरंत भुगतान करवाया जाए, कृषि व बागवानी सहायक उपकरणों स्प्रेयर, टिलर, एंटी हेल नेट पर लंबित अनुदान तुरंत दें, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का सरकार उचित मुआवजा देने के लिए ठोस नीति बने, किसानों-बागवानों के ऋण माफ किए जाएं, आधुनिक सुविधाओं से लैस विपणन मंडियां विकसित की जाएं, पुरानी मंडियों का आधुनिकीकरण हो।

सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर इसे कानूनी रूप से लागू करें, धान, गेहूं, मक्की की खरीद के लिए मंडियां स्थापित कर एमएसपी के तहत खरीद हो, निजी कंपनियों के सीए स्टोर में सेब खरीद के दाम तय करने व निगरानी को बागवानी विवि, बागवानी विभाग और बागवानों की कमेटी गठित हो, किसान सहकारी समितियों को सीए स्टोर बनाने के लिए सरकार 90 फीसदी अनुदान दे प्रदेश में सरकार भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून लागू करे, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए तथा डीजल पर वैट में की गई वृद्धि वापिस ली जाए।

पति की मौत के बाद वंदना ने संभाली जिम्मेवारी कंधों पर

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। पति की मौत से टूटकर खुद को लाचार नहीं समझा। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और न ही अपनी खुद्दारी से समझौता किया। हालात का सामना करने के लिए खुद ड्राइविंग सीट संभाली। आज वह महिलाओं के लिए मिसाल है। यहां बात हो रही है वंदना राणा की। जिन्होंने अपने पति की मौत के सात महीने के अंदर खुद को परिवार की जिम्मेदारी के लिए तैयार कर लिया। वंदना के पति राकेश राणा ऑटो चलाते थे। 18 जून 2022 को हृदयाघात के कारण उनका निधन हो गया। इसके बाद परिवार में कॉलेज पढ़ने वाली दो बेटियों की जिम्मेदारी मां पर आ गई। विपरीत हालात में उन्होंने खुद और परिवार को संभाला। जब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहा और किसी से कोई उम्मीद नहीं दिखी तो हौसले का परिचय देते हुए वंदना राणा ने दिवंगत पति के ऑटो की ड्राइविंग सीट संभाल ली। वंदना ने अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। अंब में रेल सेवा के शुरू होने के बाद से क्षेत्र में ऑटो चलने का चलन शुरू हुआ। लेकिन वर्तमान में भी क्षेत्र में अन्य कस्बों की तरह ऑटो की भरमार नहीं है। ऐसे में उत्सुकतावश एक महिला ऑटो चालक की तरफ सबकी नजर टिक जाती है। लोग उनके हौसले को सलाम करते हैं। वंदना राणा के मुताबिक उनका मायके हमीरपुर में हैं और लगभग 21 साल पहले उनका विवाह हुआ था। वह जमा दो कक्षा तक पढ़ी हैं और उनकी दो बेटियां हैं। पति की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। ऐसे में उन्होंने एक हफ्ते में ही ऑटो चलाना सीखा। जो उनके पति की मौत के बाद बेकार खड़ा था।

दो दिन बारिश और बर्फबारी के आसार

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में वीरवार और शुक्रवार को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश के अन्य जिलों में इस दौरान बारिश के आसार हैं। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। ऊंचे इलाकों की ओर न जाएं सैलानी क्रिसमस के बाद कुल्लू-मनाली और लाहौल के सिस्सू और कोकसर में नए साल के जश्न के लिए काफी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आज और कल बारिश और बर्फबारी की संभावना के चलते जिला कुल्लू के साथ लाहौल-स्पीति प्रशासन ने सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। खासकर पर्यटकों को अटल टनल रोहतांग, हामटा पास और जलोड़ी दर्रे का रुख न करने की हिदायत दी है। हिमाचल परिवहन निगम ने भी बस चालकों को खराब मौसम तथा तापमान गिरने से जम रही सड़कों पर किसी तरह का जोखिम न उठाने का आग्रह किया है। उपायुक्त लाहौल-स्पीति सुमित खिमटा ने कहा कि अगले दो दिन में सैलानी किसी भी प्रकार के जोखिम से बचने के लिए अधिक ऊंचाई, कम तापमान वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने से बचें।

हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा : मुख्यमंत्री

बोले, प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने में सभी का सहयोग आवश्यक

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। विधायक प्राथमिकता की बैठक के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में जिला सोलनए बिलासपुर और मंडी के विधायकों ने अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं के प्रस्ताव दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद योजना की यह पहली बैठक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही हैए जिसमें थोड़ा समय लगेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कड़े फैसले लेगीए जिसमें सभी का सहयोग अनिवार्य है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बदलाव करेंगे तथा प्रमुख योजनाओं को बजट में स्थान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित नई योजनाएं लाएं जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकता की बैठकें विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसमें बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव इन योजनाओं की निगरानी करते हैं और विधायक प्राथमिकता की योजनाओं की प्रगति की जानकारी विधायकों को दी जाती है।

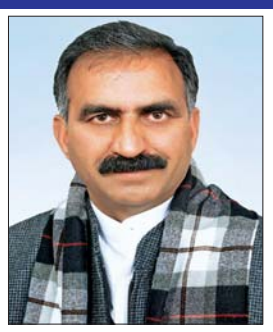

सोलन जिला नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर ने कहा कि नालागढ़ क्षेत्र में सड़क सुविधा के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है। उन्होंने रामशहर डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए धन का प्रावधान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार नालागढ़.भरतगढ़, नालागढ़.बघेरी और काला अंब.पांवटा सड़क को फोरलेन बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने तथा क्षेत्र की पेयजल परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने ट्रैफिक जाम की समस्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाएं लाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के तहत तीन कंटोनमेंट क्षेत्रों में कई पीढ़ियों से रह रहे आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं का मामला भी उठाया। विनोद सुल्तानपुरी ने कौशल्या नदी पर टिंबर ट्रेल के पास बांध और उस पर सड़क बनाने का भी आग्रह किया। वहीं झंडूता से विधायक जीत राम कटवाल ने जल संरक्षण से सिंचाई का आधारभूत ढांचा मजबूत करने, बेहतर सड़क सम्पर्क पुलों के निर्माण और रोपवे बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में जलक्रीड़ा स्थल विकसित करने का आग्रह भी किया। उन्होंने वर्तमान सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्राथमिकता देने और हरित ऊर्जा राज्य बनाने के प्रयासों की सराहना की। घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सतत् व नियोजित विकास के लिए दूरगामी योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने ग्रेविटी बेस्ड सिंचाई परियोजनाओं का निर्माणए श्रीनैना देवी और बाबा बालक नाथ जी मंदिर को गोविंद सागर झील पर रोपवे बनाकर जोड़ने का प्रस्ताव दिया। बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सीमेंट कंपनी विवाद का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ट्रक ऑपरेटरों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने अपने क्षेत्र के गांवों की सड़कों की मरम्मत कर उन्हें सुचारू बनवाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कोल डैम तथा गोबिंद सागर से पीने के पानी की योजनाओं की क्षमता को बढ़ाने का आग्रह किया।श्रीनैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने श्रीनैना देवी मंदिर में विकास कार्यों के दृष्टिगत प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने नैनादेवी में 33 केवी सब स्टेशन के निर्माण को गति प्रदान करने का आग्रह किया। ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने तथा ओलिंडा से स्वारघाट से 66 करोड़ रुपये लागत की पानी की परियोजना का निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने का आग्रह किया। बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार, संजय अवस्थीए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव अक्षय सूद, योजना सलाहकार डॉ बासु सूद, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्चधिकारी उपस्थित रहे।

शूलिनी यूनिवर्सिटी में हेल्थ, वेलनेस और लाइफस्टाइल कैंप का हुआ आयोजन

पोषण विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, भोजन में कमी और गतिहीन जीवन शैली कर रही स्वास्थ्य को प्रभावित

सोलन। स्कूल ऑफ कोर इंजीनियरिंग, शूलिनी यूनिवर्सिटी द्वारा हेल्थए वेलनेस और लाइफ़स्टाइल कैंप का आयोजन किया गय। जिसमें दिल्ली के प्रतिष्ठित वेलनेसए न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल कोच डॉ. अनीश भार्गव मुख्या वक्त थे।

लोगों को उनकी जीवन शैली और खाने की आदतों में सुधार करने में मदद करने के 20 वर्षों के अनुभव के साथए डॉ. भार्गव ने चेतावनी दी कि लोग बड़े पैमाने पर अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन के पोषण मूल्य की अनदेखी कर रहे हैं, एक गतिहीन जीवन शैली के साथ मिलकर हर दिन मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और चिंता जैसी बीमारियों को आमंत्रित करते हुए उनके स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ा रहे हैं।

उनकी टीम में नूपुर गर्ग वबिनीश गुप्ता प्रियंका महेश, समीर महेश द्वारा सहायता प्रदान की गई। डॉ.भार्गव ने शिविर में लगभग 120 कर्मचारियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन कियाए और व्यापक स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल प्रदान किया जिसमें शरीर में वसाए चमड़े के नीचे का वसाए आंत का वसा, बीएमआईए आराम करने वाला चयापचयए कंकाल की मांसपेशियों का प्रतिशत, शरीर का चयापचय आदि शामिल थाए और बाद में उन्हें अपने फिटनेस स्तर, सहनशक्ति, साथ ही तनाव सहन करने की क्षमता में सुधार करने के लिए परामर्श दिया गया ।

कराडा स्कैन मशीन का उपयोग करके स्वास्थ्य प्रोफाइल का निर्माण और मूल्यांकन किया गया और डॉ. भार्गव ने स्वास्थ्य को बदलने में उचित पोषणए जीवन शैली में बदलाव और मानसिकता में बदलाव के महत्व पर जोर दिया।

डॉ.नवसल कुमार, स्कूल ऑफ कोर इंजीनियरिंग, और स्कूल के अन्य संकाय सदस्यों के साथ-साथ मानव संसाधन कर्मचारियों ने परिसर में स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन शैली शिविर का आयोजन और समन्वय किया।

प्रदेश में एक साल के भीतर 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं होंगी स्थापित

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को वर्तमान ऊर्जा नीति में आवश्यक बदलाव लाने और पांच मेगावाट क्षमता तक की सभी सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटन के लिए खुली रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश भी करेगी। सीएम सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2023-2024 की अवधि के दौरान प्रदेश भर में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिसमें कम से कम 200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड (एचपीपीसीएल) की ओर से स्थापित की जाएंगी। इसके दृष्टिगत 70 मेगावाट क्षमता के लिए भूमि चिह्नित की जा चुकी है और अन्य स्थलों को भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा। हिमाचल में विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिससे निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा किया जा सके। हिमाचल में 150 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं निजी भागीदारी से हिम ऊर्जा स्थापित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के आवंटन में हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने हिम ऊर्जा को एक ऐसा तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 3 मेगावाट क्षमता से अधिक की सौर परियोजनाओं में राज्य को रॉयल्टी प्राप्त होने से वित्तीय लाभ मिल सकेगा। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भूमि दी जाती है तो इसके लिए उनसे इसकी हिस्सेदारी के रूप में कुछ प्रतिशत राशि भी ली जानी चाहिए। हिम ऊर्जा को पांच मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में राज्य के लिए पांच प्रतिशत प्रीमियम और पांच मेगावाट क्षमता से अधिक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 10 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। एसजेवीएनएल की हिमाचल में पांच सौर ऊर्जा परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। जिला ऊना में 112.5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना थपलान स्थापित की जा रही हैं। ऊना जिला में 20 मेगावाट क्षमता की एसपीपी भंजाल और कांगड़ा जिले के फतेहपुर में 20 मेगावाट, सिरमौर जिला में 30 मेगावाट एसपीपी कोलार और कांगड़ा जिले के राजगीर में 12.5 मेगावाट क्षमता एसपीपी की परियोजनाएं निर्माण के चरण में हैं। सरकार की योजना आगामी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 12 फीसदी तक बढ़ाने की है।

डलहौजी में सात माह बिताए थे नेताजी ने, पर्यटन स्थल से रहा है गहरा नाता

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

चम्बा। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी से आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस का गहरा नाता रहा है। वर्ष 1937 में सुभाष चंद्र बोस ने डलहौजी में लगभग सात महीने का समय बिताया और स्वास्थ्य लाभ लिया था। उनकी याद में डलहौजी के एक चौक का नाम सुभाष चौक रखा गया हैं। यहां उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है।

गांधी चौक के नजदीक सुभाष बावली नामक पर्यटक स्थल है, जहां रोजाना सुभाष चंद्र बोस बावड़ी का पानी पीते थे। गौरतलब है कि आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1937 में जब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आजादी की लड़ाई के चलते जेल में बंद थे तो उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पैरोल पर रिहा किया। सुभाष चंद्र बोस स्वास्थ्य लाभ के लिए डलहौजी आ गए। जब उनके डलहौजी आने की खबर उनके दोस्त डॉ. धर्मवीर को पता चली तो डॉ. धर्मवीर ने उन्हें उनसे डलहौजी के बंगले कायनांस में ठहरने का आग्रह किया। नेता जी लगभग सात महीने डलहौजी में रहे। रोजाना वह एक बावड़ी का पानी पीते थे, जो आज सुभाष बावली के नाम पर गांधी चौक के पास जंदरीघाट मार्ग पर स्थित है। डलहौजी के खुशनुमा मौसम से सुभाष चंद्र बोस स्वास्थ्य लाभ लौटे और आजादी की जंग में कूद पड़े। बताते हैं कि डलहौजी पहुंचने पर सुभाष चंद्र बॉस ने किसी भारतीय नाम के होटल में रुकने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनके दोस्त डॉक्टर धर्मवीर अपने बंगले में ले गए। आज भी गांधी चौक के पास पंजपुला मार्ग पर कायनांस बंगला मौजूद है।

निजी बंगला होने के कारण यहां कोई नहीं जा सकता। डलहौजी के सरकारी स्कूल का नाम भी नेता जी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल से डलहौजी में काफी पर्यटक आते हैं और नेता जी की यादों से जुड़े पर्यटक स्थलों का अवलोकन करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस की याद में डलहौजी में एक म्यूजियम होना चाहिए।

'आदर्श हिमाचल' अखबार के लिए मालिक, प्रकाशक व मुद्रक देविंद्र सिंह द्वारा सेट नं. 6, अप्पर कैयू, शिमला-3 से प्रकाशित और विज्ञापना इंटरप्राइजिज, दुर्गा काटेज, एसडीए काम्पलैक्स कुसुम्पटी से मुद्रित। आदर्श हिमाचल से संबंधित सभी मामलों का निपटारा न्यायाकि क्षेत्र शिमला में होगा। फोन नंबर-9857537874, 9418694594, 8091152022।